



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उद्धोषण (१)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)  
श्रीधराराम प्रकाशन  
PUBLISHED BY AUTHORITY

वा. ४६] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी ३०, १९९१/मार्च १०, १९१२

No. 46] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1991/MAGHA 10, 1912

इस भाग में खिल पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे यह भाग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, ३० जनवरी, १९९१

सा.या.नि. ५१ (प्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित  
उद्धोषण संविधान के सूचनार्थ प्रकाशित वी जा रही है:—

यह: मेरा, भारत के राष्ट्रपति, आर. बेंकटरामन, का यह समाधान  
हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें तमिलनाडु राज्य  
का ज्ञासन भारत के संविधान (जिसे इसमें इसके पश्चात 'संविधान'  
कहा जाता है) के उपर्योगों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

यह: मैं, संविधान के अनुच्छेद ३६६ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का  
तथा उस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली भव्य सभी शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए एतद्वारा उद्धोषण करता हूँ कि मैं:—

(क) उक्त राज्य की सरकार के सभी हस्त और उस राज्य के  
राज्यपाल में निहित, तथा उनके द्वारा प्रयोगशक्ति सभी शक्तियों  
भारत के राष्ट्रपति के रूप में स्वयं संभालता हूँ;

(ख) घोषित करता हूँ कि उक्त राज्य के विधानमंडल की  
शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के प्रधीन  
प्रयोगशक्ति होंगी; और

(ग) निम्नलिखित आनुच्छेद और पारिणामिक उपबंध करता हूँ  
जो इस उद्धोषण के उद्देश्यों को प्रभारी बनाने के लिए  
मुझे आवश्यक या आवश्यक प्रतीत होने हैं; प्रथमतः:—

(i) इस उद्धोषण के उपर्युक्त खण्ड (क) के आधार  
पर मेरे द्वारा संभाले गए हस्तों और शक्तियों का  
प्रयोग करने में, मेरे लिए, भारत के राष्ट्रपति के  
रूप में उस स्तरों तक जिस तक मैं ठीक समझूँ  
उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना  
विधिवृत्त होगा;

(ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित  
उपर्योगों के प्रवर्तन की प्रवृद्धारा सिलेक्ट किया  
जाता है, प्रथमतः:—

अनुच्छेद ३ के परन्तुक का उतना भोग जिसने का संबंध गण्डूपनि  
द्वारा राज्य के विधानमंडल की निदेश करने से है;

अनुच्छेद १५१ के खण्ड (2) का उतना भोग जिसने का संबंध भारत  
के विधान, एवं महानेता परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट  
के राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने गे हैं;

अनुच्छेद १६३ प्रारंभ १६-।;

अनुच्छेद १६६ के खण्ड (3) का उतना भोग जिसने का संबंध<sup>1</sup>  
राज्य सरकार के कार्यों का विविध शक्तियों के बीच आवंटन से है;

अनुच्छेद 167 और अनुच्छेद 169 के खंड (1) का उत्तरा भाग जितने का संवंध राज्य की विधान सभा द्वारा संकल्प के पारित किए जाने से है;

अनुच्छेद 174 का खंड (1), गो—गां (2) का उत्तर (क) ; अनुच्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) ; अनुच्छेद 179 का खंड (ख) और (ग) और उन अनुच्छेद का प्रथम अंशुक, और अनुच्छेद 180 और 181;

अनुच्छेद 186 का उत्तरा भाग जितने का संवंध विधान सभा के उपाधिकार के संबंधमें और भर्तों से है; अनुच्छेद 188, 189, 193 194, 195 तथा 196;

अनुच्छेद 199 का खंड (3) और खंड (4) ;

अनुच्छेद 202 के खंड (3) का उत्तरा भाग जितने का संवंध विधान सभा के उपाधिकार के संबंधमें और भर्तों से है; अनुच्छेद 208 व 211 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं) अनुच्छेद 213 का खंड (1) का प्रथुक, और खंड (3) का प्रथुक; और

अनुच्छेद 323 के खंड (2) का उत्तरा भाग जितने का संवंध विधान संसद रिपोर्ट की राज्य विधान संडल के समक्ष रखे जाने से है;

(iii) उत्तर राज्य का विधान सभा एवं द्वारा भर्ती जानी है;

(iv) मंविधान में राज्यपाल के प्रति किसी निवेश का अर्थ उस राज्य के संवंध में गट्टप्रति के प्रति निवेश तथा आएगा और उसमें राज्य के विधान मंडल के प्रति किसी निवेश का, जहाँ नक उसका संवंध उसके हुत्यों और उनकी भाविताओं से है, और, जब नक कि संवर्द्ध में वान्याधि अधिकार न हो, संवर्द्ध के प्रति निवेश लगाया जाएगा, और विविष्टताएँ अनुच्छेद 213 में राज्यपाल और राज्य के विधानसंडल के प्रति निवेश का अर्थ कहा गएप्रति और संसद के प्रति निवेश लगाया जाएगा :

एवं इसमें कोई भाव अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155 व अंकर अनुच्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं), अनुच्छेद 299 और अनुच्छेद 361 तथा द्वितीय अनुसूची के द्वितीय 1 गे 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलित हैं) के उपर्योग पर प्रभाव नहीं उत्पन्नी अवश्य राष्ट्रपति को इस तरह के उपर्योग (1) के वर्वान उप भीमा वर्ग जहाँ नक वह ठीक भविते उत्तर राज्य के राज्यपाल के भावधारण में कार्य करने में निर्वाचित करेंगे,

(v) मंविधान में उक्त राज्य के विधान मंडल के या एवं द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निवेश का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अतिरीक्ष हम उद्धीश्यणा के प्राचार पर संवेद द्वारा, गट्टप्रति या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपर्योग (क) । । में निविष्ट प्रथ्य प्राधिकारी द्वारा उत्तर राज्य के विधानसंडल की गणिताओं का प्रयोग करते हुए बनाए गए अधिनियम या विधियों के प्रति निवेश है, और नमिनतादु नामारण खंड अधिनियम, 1891 (1891 का नमिनतादु अधिनियम 1), जैसाकि वह नमिनतादु राज्य में वाहू है, और गाधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) का उत्तरा भाग जितना राज्य विधियों पर वाहू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में

ऐसे प्रकारी होगा मानो वह उक्त राज्य विधानसंडल का अधिनियम हो ।

नहीं विलीना,  
30 जनवरी, 1991

श्रावण केट्टरमन,  
गवर्नर

[फा. नं. V/11013/2/91-7. 15. 112]

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1991

G.S.R. 54(E).—The following Proclamation by the President is published for general information:

Whereas, I, R. Venkataraman, President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Tamil Nadu cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I —

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State;

(b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—

(i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State,

(ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:—

so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State;

so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the reports submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164;

so much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State;

article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;

clause (1), and sub-clause (a) of clause (2), of article 174; articles 175 to 178 (both inclusive) clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181;

so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; clauses (3) and (4) of article 199;

so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and

so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;

(iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved;

(iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State shall be construed as references to the President and to Parliament; respectively:

Provided that nothing herein shall affect the provisions of article 153, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State;

(v) any reference in the Constitution to Acts or laws of, or made by, the Legislature of the said State shall be construed as including a reference to Acts or laws made in exercise of the powers of the Legislature of the said State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Tamil Nadu General Clauses Act, 1891 (Tamil Nadu Act 1 of 1891), as in force in the State of Tamil Nadu, and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the said State.

New Delhi.

The 30th January, 1991.

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[No. V|11013|2|91-CSR]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1991

मा.का.नि. 55 (प्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्न लिखित आदेश सर्वतोत्तम रूप से वृक्षतार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

भारत के संविधान अनुसंधेद 356 से यथीन मेरे द्वारा आज 1991 वर्ष के जनवरी, मान के दीसवें दिन जारी की गई उद्बोधना तो खंड (ग) के उपखंड (1) का अनुसरण करते हुए, मैं एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि तमिलनाडु राज्य भरकार के सभी काल्पनिक संविधान के अधीन या उस राज्य में प्रयुक्त किसी विधि के अधीन उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियाँ, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्बोधना के खंड (क) के आधार पर उसे संभाल लिया है, राष्ट्रपति के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीक्षीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी।

नई दिल्ली,  
30 जनवरी, 1991

आर. वेंकटरामन,  
राष्ट्रपति

[ल. म V-11013/2/91-पी.एस.आर.]

आर के, मार्गी, गह सचिव

## ORDER

New Delhi, the 30th January, 1991

G.S.R. 55(E).—The following Order by the President is published for general information:—

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of January, 1991, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Tamil Nadu and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in

force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State.

New Delhi.

The 30th January, 1991.

R. VENKATARAMAN,  
PRESIDENT

[No. V|11013|2|91-CSR]

R. K. BHARGAVA, Home Secy.